RAJYA SABHA

Thursday, the 5th September, 1991/ Bhadra 14, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Satchidananda (Karnataka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Over charging on Sulphamethoxazole

*141. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:†
SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 273 given in the Rajya Sabha on the 1st August 1991, and state:

(a) whether it is a fact that over rupees 20 crores were overcharged by the formulators over a period of three years due to higher price fixation of sulphamethoxazole,

(b) whether it is a fact that producers sold the drug at a price varying between Rs. 280|- to Rs. 320|- as against Government fixed price of Rs. 390|- per kg. based on BICP Cost Study;

(c) what are the reasons for delay in reducing the prices of finished medicines based on the reduced price of bulk drugs announced on 7th March, 1991;

(d) whether it is a fact that Government have not reduced the price of number of other formulations where bulk drug prices have been reduced; and

(e) if so, names of the drugs, earlier price and reduced price of each?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. CHINTA MOHAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) Government have no reports of the sale of formulations of Sulphamethoxazole at prices higher than notified prices.

(b) As per the provisions of DPCO 1987 it is possible for a manufacturer to sell a bulk drug at a price lower than the notified prices.

(c) Pending receipt of BICP study report on Trimethoprim, reduction in price of formulation based on Sulphamethoxazole was kept in abeyance. Also, BICP sought technical clarification in regard to reductions in prices which are yet to be resolved.

(d) and (e) The requisite details, to the extent available with the Government, are given in the Annexure. Action to fix new formulation prices will be finalised soon in consultation with the BICP.

List of Bulk drugs where prices have been reduced from 1-1-91

Sl.No.	Name of Bulk Drug	Unit	Price after reduction	Previous Price
1	2		3	4
			(Rs)	(Rs)
1	Phenytoin Sodium	Kg	236·00 23-1-91	261·06 26-8-76
2	Metronidazole	Kg	428·00 1-2-91	482·00 9-9-88

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajni Ranjan Sahu.

1		2	3	4
3	Metronidazole Benzoate	Kg	380.00 1-2-91	511.00 25-1-85
4	Ibuprofen	Kg	450.00 1-2-91	502.00 27-6-89
5	Amoxicilin Trihydrate	Kg	2093.00 11-2-91	2660.00 21-3-89
6.	Analgin	Kg	251.00 26-2-91	280.00 1-6-90
7	Sulphacetamide	Kg	350.00 7-3-91	35.00 20-6-89
8	Sulphamethoxazole	Kg	340.00 7-3-91	350.00 16-2-83
9	Methyl Dopa	Kg	1967.00 7-3-91	4148.00 20-1-86
10	Isoxuprine	Kg	6401.00 7-3-91	8997.00 19-9-84
11	Sulphamoxole	Kg	390.00 3-6-91	430.00 11-10-81

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि पहली बार मेरा सवाल प्रथम नम्बर पर आया है, स्टार्ड क्वश्चिन ।

श्री सभापति : इसके सिलसिले में सारे हाउस को आप मिठाई खिलाने वाले हैं ।

श्री रजनी रंजन साहू : महोदय, पिछले सालों से मेरा यह प्रयास चलता रहा है कि गरीबों को एवं आम जनता को उचित मूल्य पर दवा मिले । उसी संदर्भ में मैंने यह प्रश्न पूछा था लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने प्रश्न नहीं समझा और उत्तर ठीक-ठीक नहीं दिया । मैंने कहीं पर नहीं पूछा है कि सल्फामीथोक्साजोल के सूत्रधारों की अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बिक्री होने की कोई रिपोर्ट सरकार के पास है या नहीं ? मैंने यह पूछा था कि सल्फामीथोक्साजोल की बढ़ी हुई कीमत के कारण दवा कम्पनियां 20 करोड़ रुपये से ज्यादा गरीबों से वसूल चुकी है, इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं ? महोदय, इसकी जानकारी सरकार को है, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस दवा की कीमत बी०आई०सी०पी० ने 390 रुपये से घटाकर 340 रुपये कर दी । यह इन्होंने इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है और इनको 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इफेक्ट देना था ।

महोदय, 198 में डी०पी०सी०ओ० बना और उसके बाद जो कीमत निर्धारित की गई, उसके मुताबिक अनेक दवाओं के दाम तय करने थे और उनमें यह दवा भी थी । महोदय, 198 से लेकर अगस्त 1988 तक वह फाइल बी०आई०सी०पी० के पास पड़ी रही और जिस दवा पर डी०पी०सी०ओ० ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कीमत कम की, उस पर बी०आई०सी०पी० ने कोई जवाब नहीं दिया और वह फाइल उसके पास दो साल तक पड़ी रही । दो साल बाद बी०आ ०सी०पी० ने मार्च, 1991 में स्वीकृति दी कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका दाम कम होना चाहिये । महोदय, इस तरह चार साल तक उद्योगपतियों ने और जो बल्क ड्रग

बनाने वाले मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं, इन दोनों ने इसका पूरा-पूरा उपयोग किया और 20 करोड़ रुपये उन्होंने गरीबों से वसूले। सरकार को इसकी जानकारी भी है और सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है कि प्राइस जो कम किया गया, उसका इफेक्ट देने जा रहे हैं। यह पहले के प्रश्नों में आ चुका है और मैं उन प्रश्नों का हवाला नहीं देना चाहता हूं लेकिन वे प्रश्न इसी सदन में पूछे गये हैं। एक प्रश्न है । अगस्त, 1991 का और उससे पहले मार्च में एक प्रश्न में यह बात आई है । खैर, अब मैं सवाल पर आता हूं।

डा० बापू कालदाते : इतनी देर तक क्या कर रहे थे।

श्री प्रमोद महाजन : पहली बार प्रथम नम्बर पर सवाल है।

डा० बापू कालदाते : इसलिये इतना लम्बा कह रहे हैं।

श्री रजनी रंजन साहू : आपको समझाने के लिए यह आवश्यक है।

डा० बापू कालदाते : हम समझ गये, उनको समझाइये।

श्री रजनी रंजन साहू : मेरा प्रश्न यह है कि चार सालों तक यह जो फाइल ब्यूरोक्रेसी के पास घूमती रही, कैमिकल मिनिस्ट्री से बी० आई० सी० पी० फिर बी० आई० सी० पी० से कैमिकल मिनिस्ट्री, इस बीच इन चार सालों तक जो उपभोक्ताओं को लूटा गया, उसके लिये सरकार किसको उत्तरदायी ठहराती है और ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने इन फाइलों को डिले किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का आश्वासन मंत्री महोदय देंगे, क्योंकि जब किसी दवाई का दाम बढ़ाया जाता है, तो उसका इफेक्ट एक महीने के अन्दर उद्योगपतियों को मिल जाता है और जब कमाया जाता है, तो उपभोक्ता को कभी नहीं मिलता है । महोदय, बड़े मार्के की बात है । जब बढ़ाया जाता है, तो मिल जाता है, जब कमाया जाता है तो नहीं मिलता है । इसलिय मेरा प्रश्न यह है कि इसमें ब्यूरोक्रसी के जो भी पदाधिकारी इन्वाल्व हैं, जो इन पांच सालों में इन्वाल्व रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई जांच समिति मंत्री महोदय बिठाएंगे ?

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, I understood the hard words of the hon. Member of Parliament. I will call for a report from the BICP. Only after getting a positive reply from the BICP will I try to implement it. He mentioned about an officer involved. If he can give the specific reference, we will take action.

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, बी० आई० सी० पी० ने तो अपनी अनुशंसा दे दी (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I draw your attention to the inadequate reply by the Minister. This question is being discussed in the House by Mr. Sahu and friends for the last six years. Mr. Sahu has alleged that there has been an overcharge of about Rs. 800 crores by various drug companies, and now the Minister says that he is going to the BICP! Such a reply.....

SHRI DIPEN GHOSH: The charge is against the BICP and he will collect the information from the BICP.

SHRI A. G. KULKARNI: Only one minute, Sir. We have digested such replies for the last six years. There must be some way out to make the Government take action against the offender, and only you can do that.

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, मैंने यह सवाल पूछा कि चार साल का डिले हुआ, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था कंज्यूमर्स को वह नहीं मिला सरकारी फाइलों में डिले की वजह से नहीं मिला । दो-दो साल तक फाइल एक जगह पड़ी रही । क्या वैसे पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच समिति मंत्री जी बनाएंगे ? इसमें भी इनको दिक्कत हो रही है । जहां सरकार की गड़बड़ी होती है उसको भी ठीक नहीं करेंगे, पैसा भी नहीं देंगे तो यह कैसे चलेगा ? जो उद्योगपति, जो लोग गरीबों से पैसा लूटते हैं और जो अफसर उनके साथ मिले हुए हैं, उनको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ? महोदय, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और इनसे उत्तर खिंचवाकर दीजिए ।

SHRI A. G. KULKARNI: You have heard this reply so many times for the last five years.

SHRI CHINTA MOHAN: I have requested the hon. Member to give the specific instance of the officer who is involved in this. If he can give that, immediately we can take action.

श्री रजनी रंजन साहू : यह फ़ाइल किसके पास है ? 1987 से लेकर 89 तक क्यों रखी रही ? और 1989 से लेकर 91 तक किस लिए रखी रही ?

श्री सभापति : एक ही अफसर था क्या ? मंत्री तो बदल गये ।

श्री रजनी रंजन साहू : एक ही अफसर होता है । ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होता है । (व्यवधान)

श्री सभापति : यह कहते हैं एक ही अफसर है । बदला नहीं है । He says that one person kept the file for 6 to 7 years.

SHRI DIPEN GHOSH: May I know from the Minister whether the responsibility would be fixed on that person who kept the file for 6 years? ..(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: He wants that that man should be punished.

कामेंटरी मत कीजिए । (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI: We waited for the Congress Government to return to power so that justice is meted out. ..(*Interruptions*) ..You direct him.

MR. CHAIRMAN: He says that he will enquire into the whole thing.

SHRI A. G. KULKARNI: After the enquiry, he should place the report on the Table of the House.

डा० बापू कालदाते : यह 6–6 साल से चल रहा है । लगातार 6 साल से मामला चल रहा है । क्या इंक्वायरी कर रहे हैं आप ? 800 करोड़ रुपये is involved in it. What the hell they are doing?

SHRI JAGESH DESAI: These multinational corporations are looting the people of the country.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, why don't you help us?

MR. CHAIRMAN: He has understood it. He has followed the sense of the House. He himself was a medical practitioner. He understands everything. When he has promised, he will look into it...(*Interruptions*).

SHRI A. G. KULKARNI: What is meant by "looking into it"? To me it means nothing will happen.

MR. CHAIRMAN: I trust every Member of the Rajya Sabha, whether he is sitting this side or that side or whether he is in the Government or wherever he is..(*Interruptions*).. I trust every Member of the House.

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, कम से कम इतना तो कहिये उनसे कि दो महीने में जवाब दें, एक महीने में जवाब दें। 6 साल से लगातार यह मामला चल रहा है (व्यवधान)

श्री सभापति : जल्दी कर देंगे । (व्यवधान)

डा० बापू कालदाते : 6 साल तो हो गए जल्दी कब तक करेंगे ? बताइये यह कब तक देंगे asking him, through you, कितने दिन में देंगे ?

SHRI A. G. KULKARNI: That money must be recovered. ..(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: He himself was a medical practitioner.

DR. BAPU KALDATE: Why doesn't he say about the time-limit?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इनका जवाब...

श्री सभापति : क्वेश्चन चलने दीजिए । माथुर साहब आप सीनियर आदमी हैं । आप तो मत करिये । देखिये सिन्हा साहब चले गये । (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इनके जवाब से मामला एश्योरेंस को चला जायेगा और फिर मामला लटक जायेगा । हम चाहते हैं कि एश्योरेंस कमेटी के पास जाने से पहले जवाब आ जाय । (व्यवधान)

श्री सभापति : कोशिश करेंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एश्योरेंस कमेटी में चला जायगा तो मामला लटक जायगा ।

डा० बापू कालदाते : कोशिश करने का मामला हमारी समझ में नहीं आ रहा है । इनको कहना चाहिए कि महीने में दें, दो महीने में दें... (व्यवधान)

श्री सभापति : कोशिश के बिना कामयाबी कहां होगी । पहले कोशिश होती है फिर कामयाबी होती है । (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है.... (व्यवधान) He says "The matter is being looked into. ..." ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: He said that he will expedite it.

श्री रजनी रंजन साहू : कल इसी पर बेकल उत्साही जी शेर बना रहे थे...

श्री सभापति : आप सवाल कर रहे हैं या शेर पढ़ रहे हैं । शेर पढ़ना है तो सेन्ट्रल हाल में जाइये । (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू : श्रीमन, मेरा सवाल यह है कि 30 अप्रैल, 1990 को एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने सदन को कुछ आश्वासन दिये थे ।

श्री सभापति : आप आश्वासन कमेटी को याद दिला दीजिये ।

श्री रजनी रंजन साहू : उस आश्वासन में जिन जिन दवाओं की कीमतें बढ़ी उसका तो ईफेक्ट मिल गया है, लेकिन जिन दवाओं की कीमतें घटी हैं उनका ईफेक्ट नहीं दिया गया है । वह मंत्री जी कब तक दे देंगे ?

MR. CHAIRMAN: He says where the prices have been increased, they have been given effect to. But they are not being implemented where they are reduced.

SHRI CHINTA MOHAN: Within a week's time we will try to implement it.

MR. CHAIRMAN: Good.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, I have a supplementary.

MR. CHAIRMAN: You have already put your supplementary.

SHRI DIPEN GHOSH: This is an important supplementary coming out of it.

MR. CHAIRMAN: All right. Now, Smt. Satya Bahin.

श्रीमती सत्या बहिन : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि बल्क ड्रग्ज का पहले जो मूल्य था उसको 21 मार्च, 1989 को फिर से घोषित किया गया और फिनिश्ड मेडिसिन्स के मूल्य 7 जनवरी, 1991 को एक साल दस महीने बाद घोषित किये गये । इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि इस बीच के समय में जनता से जो पैसा वसूल किया गया उसको आप कैसे वापस करेंगे और इस संबंध में मंत्री जी का क्या कहना है ? दूसरा इसी से संबंधित मेरा प्रश्न यह है कि बी० आई० सी० पी० द्वारा मूल्यों में कमी के संबंध में जो तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे गये हैं उसकी समय सीमा क्या रखी गई है और उसको कब तक ये तकनीकी स्पष्टीकरण दे दिये जायेंगे और इसकी घोषणा आप कब तक करेंगे ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इम्पोर्टेड ड्रग्ज की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वे तब बढ़ाई गई जब सदन का सत्र चल रहा था, इसलिए सदन को बिना विश्वास में लिये किस आधार पर इम्पोर्टेड ड्रग्ज की कीमतें बढ़ाई गई हैं ?

SHRI CHINTA MOHAN: We have implemented it as per the DPCO of 1987. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: He is a doctor himself. He is a medical doctor. (*Interruptions*).

SHRI A. G. KULKARNI: He is a very quick-fix doctor.

MR. CHAIRMAN: He provides effective medicines.

SHRI A. G. KULKARNI: How can you say they are effective?

MR. CHAIRMAN: They are fast acting effective medicines. (*Interruptions*).

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, the supplementary raised by Mr. Sahu was in connection with the delay... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: It is a supplementary to the supplementary.

SHRI DIPEN GHOSH: Part (c) of the question was: "What are the reasons for the delay in reducing the prices of finished medicines based on the reduced price of bulk drugs announced on 7th March 1991?" The Government has taken, at least the BICP has taken, two years to declare the reduced prices of bulk drugs. But the prices of formulations are fixed on the prices of bulk drugs declared by the Government and not on the prices of bulk drugs as purchased from the market. Bulk drugs were kept at a higher prices, Rs. 390 per Kg. for all these years. When the prices of formulations are fixed, naturally they are fixed on the basis of the higher bulk drug prices declared by the Government. They also take further time. The Government takes further time to decide the prices of formulations. Even though they declare a reduction in bulk drug prices after two or three years, the benefit of that reduction in bulk drug prices does not percolate down to the prices of formulations and now they are kept in abeyance. My supplementary is whether the Government proposes to decide a norm by which as soon as the prices of bulk drugs are reduced or increased, the prices of formulations will also be refixed.

SHRI CHINTA MOHAN: We will try to implement it, Sir.

MR. CHAIRMAN: Your suggestion will be taken note of.

SHRI KAMAL MORARKA: I want to know from the Minister whether there is any proposal before the Government to abolish the DPCO. I have read it in the newspaper. If it is so, then all these questions become irrelevant. I would like to know whether in this new policy of liberalisation there is any proposal to do away with the control altogether before the Government. I would like to have a categorical answer.

SHRI CHINTA MOHAN: At present, no such proposal is there with the Government.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Sir, though the Ministry received the recommendations of reduction of price of Sulphamethoxazole in 1989, it did not take action on the recommendations. The Ministry did not reduce the price of the drug and decided to maintain the old price which gave effect to the recommendations of increased prices. The point arises that when the Government has received the recommendations for reduction of price of drug from Rs. 390 per kg. to Rs. 340 per kg, why it has been decided to maintain the old price of Rs. 390 per kg. What does it show? Is it not injustice to poor consumers? Why is this disparity?

SHRI CHINTA MOHAN: Sir, for the benefit of the House, I would like to make a few points. I have gone through the entire bulk drug pricing and the formulations etc. For example, a tablet of septran—400 mgs as we take it—today the 400 mgs septran is costing about Rs. 0.73 in retail and because of this bulk drug reduction, the price may come down by 4 paise or 2 paise. That is all the effect of this. In the context of devaluation, it appears to be very microscopic and if the House says that it should be implemented, we are ready to implement it.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, I would like to quote certain figures from the Annexure. As regards item no. 10 in the Annexure, it says, the price was reduced from Rs. 8997 to Rs. 6401. That means it has been reduced by abou

Rs. 2680 per kg. Similarly, in case of item on. 5, it was reduced from Rs. 2660 to Rs. 2093. So it has been reduced by 35 per cent to 40 per cent. For so many years they have looted the people of this country. If it is profiteering, will the Government proceed against all these people so that those who want to play with the lives of the people can be sent to jail and then their picture could be shown to the people that we are committed to his? For so many years, they have sucked the blood of the people. So if it is profiteering, then will the Government prosecute them and send them to jail?

SHRI CHINTA MOHAN: We will examine this, Sir.

Identification of locations for electronic projects

*142. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have identified suitable locations for the Electronic Trade and Technology Development Corporation to promote a VCR/VCP manufacturing project and the third unit of the Electronic Switching System in Rajasthan;

(b) if so what are the details thereof and when was the request from the Government of Rajasthan received in this regard; and

(c) by when the decision is likely to be taken by the Central Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

The Government of Rajasthan, vide communications dated August 10, 1989 and January 15, 1991 approached the Central Government regarding setting up of the VCR/VCP manufacturing Project by Electronic Trade & Technology Development Corporation (ET&T) in Rajasthan. The proposal of ET&T for setting up of VCR/VCP manufacturing project has not been approved by the Government.

A proposal for setting up of a Electronic Switching System (ESS) C-DOT MAX-512 port Factory in Rajasthan was received by the Department of Telecommunications from Rajasthan Communication Limited, Jaipur, a State Public Sector Undertaking in February, 1991. This proposal has not been considered by the Government as there are simliar manufacturing units already in production in Rajasthan. However, under the new industrial policy, no industrial licence is required at present for this item.

श्री राम दास अग्रवाल : सभापति महोदय मेरे प्रश्न का जो उत्तर मिला, मुझे उससे बड़ी निराशा हुई यह सरकार नयी हो सकती है लेकिन जो जवाब देने वाले लोग हैं, वे तो बहुत पुराने हैं । यह उत्तर शायद तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है और सरकार ने उत्तर देने के पहले इसकी जानकारी नहीं की है कि वास्तविकता क्या है । महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ पता नहीं क्यों एक सौतेला व्यवहार प्रारम्भ से ही चल रहा है । राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके इनवेस्टमेंट के हिसाब से केवल दो प्रतिशत राजस्थान में इनवेस्टमेंट किया गया है जबकि हमारी पापुलेशन हिन्दुस्तान की कुल पापुलेशन का पांच प्रतिशत है और क्षेत्रफल 10 प्रतिशत है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर गत 40 वर्षों से राजस्थान के साथ इस प्रकार का औद्योगिकीकरण में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है । इसी उत्तर में मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई कि जो कुछ भी मैंने इलेक्ट्रोनिक उद्योग के बारे में पूछा उसका उत्तर केवल ना में है, कहीं पर हां में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो टीम राजस्थान में गई थी इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग सिस्टम के लिए उसकी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, 125 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो कि आई० टी० आई० द्वारा लगाया जाना था, उसका सब प्रकार से अध्ययन कर लिया गया है लेकिन इसमें हमारी सरकार ने जो उत्तर दिया है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि निराशा हुई, ऐसे कई उद्योग राजस्थान में काम कर रहे